भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1144
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 28 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

2030 तक सभी वाहनों का इलेक्ट्रिक होना

1144. श्री सी.एम.रमेश :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2030 तक देश में सभी वाहनों का इलेक्ट्रिक होना व्यावहारिक तौर पर संभव है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; विद्युत; वित्त इत्यादि मंत्रियों के बीच इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): वर्तमान में, देश में सभी वाहनों को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है। इस स्कीम के चरण-I, जो मूलतः 01 अप्रैल, 2015 से आरम्भ होकर 2 वर्ष की अवधि के लिए था, कार्यान्वयनाधीन है। हालांकि, चरण-I का विस्तार स्कीम के अंतर्गत माइल्ड हाइब्रिड प्रौद्योगिकी को होने वाले उपलब्ध लाभ को 01 अप्रैल, 2017 से समाप्त करने के आंशिक संशोधन के साथ 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए कर दिया गया था। यह स्कीम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 की पूर्ति हेतु तैयार की गई थी।

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विद्युत; वित्त आदि के मंत्रियों के साथ हाल ही में कोई बैठक नहीं की है।

******